

Daily News Analysis



- **BHIM 3.0 – डिजिटल भुगतान**
- **स्वर्ण मुद्राकरण योजना**
- **भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र**
- **मानसून और क्लाउड बैंड**
- **रक्षा स्वदेशीकरण और नवाचार**
- **Prelims Fact (short News)**

28 March 2025, 8 AM



THE HINDU

The Indian **EXPRESS**
JOURNALISM OF COURAGE

Indian Business Times

DELIVERING INDIAN BUSINESS STORIES



businessline.

**परीक्षा उपयोगी न्यूज़ और
एडिटोरियल की हिंदी व्याख्या**

News Analysis

1. भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र: विकास, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ
2. सीसा विषाक्तता: एक गंभीर स्वास्थ्य संकट
3. भारत में रक्षा स्वदेशीकरण और नवाचार: आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम
4. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): क्या है और क्यों चर्चा में है?
5. भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का सतत उपयोग: वर्तमान प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की राह

Short news

1. मानसून और क्लाउड बैंड: प्रभाव और अध्ययन निष्कर्ष
2. सहयोग पोर्टल और एक्स कॉर्प का विरोध
3. BHIM 3.0 – डिजिटल भुगतान का नया युग
4. स्वर्ण मुद्राकरण योजना – महत्वपूर्ण बदलाव
5. बायोसारथी मेंटरशिप पहल और भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

1. भारत का ऑटोमोबाइल क्षेत्र: विकास, उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ

**Press Information Bureau**

 About Us ▾ Press Releases ▾ Gallery ▾ Explaners ▾ Media Facilitation ▾ Archives ▾ Fact Check Unit ▾

Home / All Explaners / EXPLAINER DETAILS

Ministry of Commerce & Industry

Revolutionizing Mobility The Make in India Auto Story

Posted On: 25 MAR 2025 5:33PM

Key Takeaways

Make in India has boosted domestic car production and EV manufacturing.

The automobile sector contributes approximately 6% to India's national GDP

Vehicle production grew from 2 million (1991-92) to 28 million (2023-24).

Automobile exports reached 4.5 million units in FY 2023-24.

US \$36 billion FDI attracted in the past four years.

4.4 million EVs registered, with 6.6% market penetration.

PLI & PM E-DRIVE schemes supporting EV and battery manufacturing.

GST on EVs reduced from 12% to 5%.

India's auto component sector contributes 2.3% to GDP and employs 1.5 million people directly.

The sector grew at a CAGR of 8.63% from FY16-FY24.

Exports reached US\$ 21.2 billion in FY24 and are projected to hit US\$ 30 billion by 2026.

The government is actively promoting electric mobility and advanced automotive technologies.

क्यों चर्चा में है?

भारत का ऑटोमोबाइल उद्योग 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत 2023-24 में रिकॉर्ड वृद्धि पर पहुँचा। कुल वाहन उत्पादन 28 मिलियन यूनिट तक पहुँच गया, जिससे भारत वैश्विक इलेक्ट्रिक वाहन (EV) विनिर्माण केंद्र बनने की ओर अग्रसर है।

विकास यात्रा

- **1991 के बाद उदारीकरण:** लाइसेंस मुक्त नीति और 100% FDI की अनुमति से विदेशी कंपनियों (सुजुकी, हुंडई, होंडा आदि) का आगमन हुआ।
- **तेजी से उत्पादन वृद्धि:** 1991-92 में 2 मिलियन यूनिट से बढ़कर 2023-24 में 28 मिलियन यूनिट।
- **अर्थव्यवस्था में योगदान:**
 - उद्योग का कुल कारोबार **240 बिलियन डॉलर**।
 - भारत के **GDP में 6%** योगदान।
 - **30 मिलियन रोजगार सृजन** (4.2 मिलियन प्रत्यक्ष, 26.5 मिलियन अप्रत्यक्ष)।
- **ऑटो कंपोनेंट उद्योग:**
 - GDP में **2.3%** योगदान।
 - 2023-24 में कारोबार **74.1 बिलियन डॉलर**।
 - **8.63% की वार्षिक वृद्धि दर** से निर्यात बढ़कर 21.2 बिलियन डॉलर हुआ, जो 2026 तक **30 बिलियन डॉलर** होने का अनुमान।

- EV सेक्टर की बढ़त:
 - अगस्त 2024 तक 4.4 मिलियन EV पंजीकरण।
 - EV का बाजार में 6.6% योगदान।

व्यापार और निवेश

- 2023-24 में भारत ने 4.5 मिलियन वाहन निर्यात किए।
- 21.2 बिलियन डॉलर के ऑटो कंपोनेंट निर्यात, और 20.9 बिलियन डॉलर के आयात के साथ 300 मिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष।
- FDI आकर्षण:
 - 2020-24 में 36 बिलियन डॉलर का निवेश।
 - EV और स्वचालित ट्रांसमिशन तकनीक में 7 बिलियन डॉलर का प्रस्तावित निवेश।

'मेक इन इंडिया' के तहत प्रमुख पहलें

- ✓ FAME-II योजना: 16.15 लाख EV के लिए प्रोत्साहन और 10,985 चार्जिंग स्टेशन।
- ✓ PLI योजना: EV, हाइड्रोजन फ्यूल-सेल और उन्नत तकनीकों को बढ़ावा।
- ✓ PM ई-बस योजना: 38,000 से अधिक ई-बसों की सुविधा।
- ✓ EV चार्जिंग नियम: निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन अनिवार्य।

चुनौतियाँ

-  आयात निर्भरता: EV बैटरियों और सेमीकंडक्टर का आयात महंगा और अस्थिर।
-  EV का धीमा प्रसार: वैश्विक औसत 12%, चीन में 30%, जबकि भारत में कम।
-  चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी: ग्रामीण क्षेत्रों में EV चार्जिंग की समस्या।
-  कुशल कार्यबल की कमी: स्वचालन और हाइड्रोजन तकनीक में दक्षता की जरूरत।
-  सख्त उत्सर्जन मानक: 2027-32 के CAFE III और IV नियमों से कारों की लागत बढ़ सकती है।
-  पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रभाव: राइड-शेयरिंग और मेट्रो सेवाओं से निजी वाहन मांग प्रभावित।

आगे की राह

- ✓ घरेलू उत्पादन बढ़ाना: लिथियम, दुर्लभ धातु और बैटरी निर्माण पर ध्यान।
- ✓ EV चार्जिंग विस्तार: स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के साथ चार्जिंग हब बनाना।
- ✓ ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा: MSME और स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता।

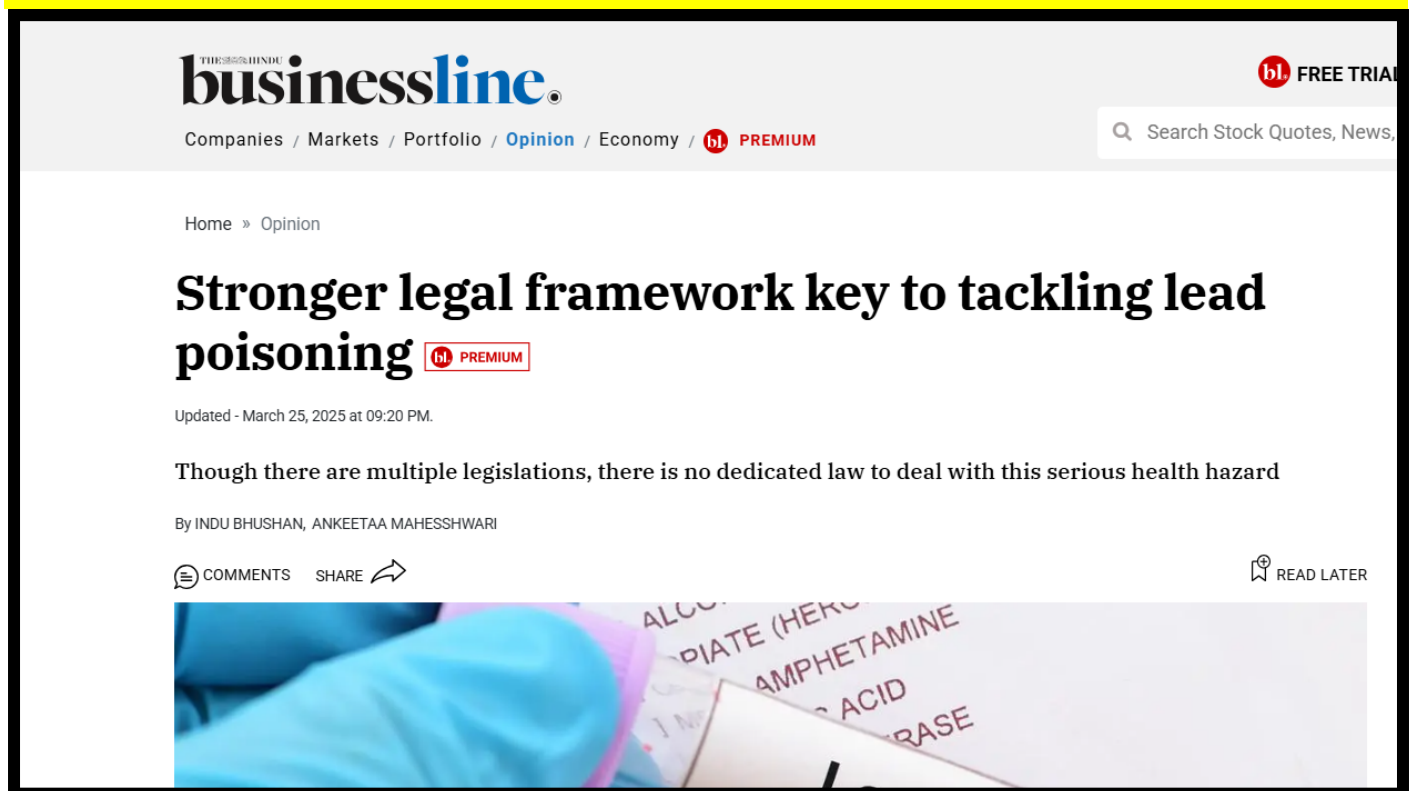
✓ EV सर्कुलर इकोनॉमी: बैटरी स्वेपिंग नीति लागू करना।

✓ EV खरीद प्रोत्साहन: स्क्रैपेज पॉलिसी से पुराने पेट्रोल-डीजल वाहनों का रिटायरमेंट।

🧠 भविष्य की संभावनाएँ

अगर सरकार EV और स्वच्छ तकनीकों में निवेश बढ़ाती है, तो 2030 तक EV का प्रसार 20% तक पहुँच सकता है और भारत ऑटोमोबाइल क्षेत्र में वैश्विक लीडर बन सकता है। 🚀

2. सीसा विषाक्तता: एक गंभीर स्वास्थ्य संकट



The screenshot shows a Businessline article. The header includes the Businessline logo, navigation links (Companies, Markets, Portfolio, Opinion, Economy), and a search bar. The article title is "Stronger legal framework key to tackling lead poisoning" with a "PREMIUM" tag. It is dated March 25, 2025, at 09:20 PM. The byline is "By INDU BHUSHAN, ANKEETAA MAHESHWARI". There are icons for comments, share, and read later. The image shows a person in a blue lab coat holding a document with chemical names like "ALCOHOL", "PIATE (HEROIN)", "AMPHETAMINE", "ACID", and "BASE".

📍 चर्चा में क्यों?

सीसा विषाक्तता भारत में एक गंभीर लेकिन अनदेखी स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है, खासकर बच्चों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, इसे रोकने के लिए कई कानून मौजूद हैं, लेकिन इनके प्रभावी क्रियान्वयन की कमी बड़ी बाधा है।

❑ सीसा क्या है?

सीसा एक भारी धातु है, जिसका उपयोग बैटरी, पेंट, कीटनाशकों और पाइपों में होता है। यह अत्यंत विषैला है, और शरीर में इसका कोई सुरक्षित स्तर निर्धारित नहीं किया गया है।

🌐 वैश्विक परिप्रेक्ष्य

WHO ने इसे 10 सबसे खतरनाक रसायनों में शामिल किया है।

2021 में जारी गाइडलाइंस के अनुसार, यदि रक्त में सीसा स्तर (BLL) $5 \mu\text{g/dL}$ से अधिक हो, तो उसके स्रोत की पहचान और उन्मूलन किया जाना चाहिए।

⚠️ सीसा विषाक्तता क्या है?

👉 जब सीसा शरीर में लंबे समय तक जमा होता है, तो यह कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है।

👉 2020 की UNICEF रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 275 मिलियन बच्चों का BLL सुरक्षित सीमा ($5 \mu\text{g/dL}$) से अधिक है।

👉 64.3 मिलियन बच्चों में यह स्तर $10 \mu\text{g/dL}$ से भी अधिक पाया गया है।

👉 भारत को इससे 5% GDP का नुकसान होता है।

🔍 सीसा विषाक्तता के लक्षण

😓 थकान, सिरदर्द,

😓 मतली, भूख न लगना,

😓 एनीमिया, मांसपेशियों में कमजोरी,

☐ मसूड़ों पर काली रेखा।

🏠 सीसा के प्रमुख स्रोत

- सीसा-आधारित पेंट 🎨
- सीसा बैटरियों का पुनर्चक्रण 🗑️
- सीसा युक्त पानी की पाइपें 🏠
- कीटनाशक और खाद्य प्रदूषण 🌾

📄 भारत में प्रमुख कानून और नीतियाँ

- ✓ सीसा पेट्रोल प्रतिबंध (2000) – पर्यावरण को स्वच्छ बनाया।
- ✓ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 – सीसा प्रदूषण पर नियंत्रण।
- ✓ कारखाना अधिनियम, 1948 – श्रमिकों की सुरक्षा।
- ✓ खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2006 – भोजन में सीसे की सीमा तय।
- ✓ PVC पाइपों के लिए नियम (2021) – जल में सीसा रोकथाम।
- ✓ बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 – बैटरियों के सही निपटान के लिए दिशा-निर्देश।

मुख्य चुनौतियाँ

- ✗ खाद्य उत्पादों (जैसे हल्दी) में सीसे की सीमा अभी भी अधिक।
- ✗ पुरानी इमारतों में सीसा पेंट का प्रबंधन नहीं किया गया।
- ✗ सीसा पाइप प्रतिबंध का सही कार्यान्वयन नहीं हुआ।
- ✗ निगरानी और प्रवर्तन तंत्र कमजोर।

आगे की राह

- ✓ मजबूत कानून और प्रवर्तन – सख्त नियंत्रण और निगरानी।
- ✓ BLL का राष्ट्रीय मानक तय करना – WHO गाइडलाइंस के अनुसार।
- ✓ श्रमिकों की सुरक्षा – अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन।
- ✓ जागरूकता और कर प्रोत्साहन – सीसा-मुक्त उत्पादों को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

सीसा विषाक्तता सिर्फ पर्यावरण नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी भारी प्रभाव डालती है। इसे रोकने के लिए कठोर कानून, प्रभावी क्रियान्वयन और जन-जागरूकता बेहद जरूरी है। भारत को इसे लोक स्वास्थ्य प्राथमिकताओं में शामिल करना चाहिए। 

3. सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF): क्या है और क्यों चर्चा में है?

SENSEX 77,984.38 +1,078.87

NIFTY 23,658.35 +307.95

CRUDEOIL 5,906.00 +6.00

GOLD 87,703.00 -75.00

SILVER 98,118.00 +234.00

businessline

Companies / Markets / Portfolio / Opinion / Economy / PREMIUM

bl. FREE TRIAL

SUBSCRIBE

LOGIN

Q Search Stock Quotes, News, Mutual Funds and More

MENU

Home » Markets

Private capex share in gross fixed capital formation drops to a decade-low 33% in FY24: ICRA

Updated - March 24, 2025 at 06:21 PM.

Notwithstanding a moderation from 28 per cent in FY23 to 12 per cent in FY24, capex by listed entities continued to record a growth

BY BL MUMBAI BUREAU

COMMENTS

SHARE

READ LATER

Union Bank

Your home's next achievement: Green building certificate through

Union Green Home

चर्चा का कारण

वित्त वर्ष 2024 में भारत के सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) में निजी पूंजीगत व्यय (Capex) की हिस्सेदारी घटकर 33% हो गई, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे कम है।

GFCF क्या है?

- ✓ GFCF का मतलब अर्थव्यवस्था में स्थायी परिसंपत्तियों (जैसे - बुनियादी ढाँचा, मशीनरी, उपकरण) में किया गया निवेश है।
- ✓ यह देश के सकल पूंजी निर्माण (GCF) का हिस्सा है और आर्थिक विकास को दर्शाता है।
- ✓ भारत के GDP में इसका योगदान 30% है, जो इसे दूसरा सबसे बड़ा घटक बनाता है।
- ✓ इसका निजी क्षेत्र के आत्मनिर्भरता और औद्योगिक नवाचार में बड़ा योगदान है।

GFCF की मौजूदा स्थिति

- 📉 2015-2024 के बीच GFCF की औसत वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) 10% थी।
- 📉 लेकिन वित्त वर्ष 2023 में 20% वृद्धि के बाद 2024 में यह घटकर 9% रह गई।

GFCF में गिरावट के कारण

- 💎 निजी पूंजीगत व्यय में कमी – वित्त वर्ष 2024 में यह सिर्फ 33% रह गया।
- 💎 ग्लोबल मंदी – भारतीय उत्पादों की निर्यात मांग घटी।
- 💎 चीनी आयात से प्रतिस्पर्धा – विशेष रूप से कपड़ा, खिलौने जैसे उद्योगों पर असर।
- 💎 कंपनियों की प्राथमिकता बदली – नई परिसंपत्तियों में निवेश की बजाय ऋण चुकाने पर जोर दिया।

GFCF में गिरावट के प्रभाव

- ⚠️ कम निवेश → उत्पादन क्षमता में गिरावट → रोजगार सृजन पर असर।
 - ⚠️ बुनियादी ढाँचा विकास धीमा → निवेशकों का विश्वास कमजोर।
 - ⚠️ FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) घट सकता है।
 - ⚠️ सरकारी खर्च पर बढ़ती निर्भरता, जो स्थायी नहीं है।
-

GFCF को पुनर्जीवित करने के उपाय

✓ ग्रामीण उपभोग को बढ़ाना

- 8वां वेतन आयोग लागू करना और मनरेगा मजदूरी बढ़ाना।
- इससे ग्रामीण क्षेत्रों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

✓ निर्यात और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना

- UK और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को अंतिम रूप देना।
- चीनी आयात पर नियंत्रण – MSME को समर्थन देने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाना।

✓ अनुसंधान और नवाचार में निवेश

- 1 लाख करोड़ रुपए के नवाचार कोष (बजट 2024-25) को लागू करना।
- इससे नई तकनीकों का विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती आएगी।

✓ औद्योगिक अवसंरचना को बढ़ावा

- आतिथ्य क्षेत्र को अवसंरचना का दर्जा देकर निजी निवेश आकर्षित करना।

✓ सतत विकास और हरित वित्त (Green Finance)

- सॉवरेन ग्रीन बॉण्ड के जरिए जलवायु-अनुकूलन परियोजनाओं को वित्तपोषित करना।
- कार्बन ट्रेडिंग और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना।

निष्कर्ष

→ GFCF में गिरावट अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह रोजगार, उत्पादन और निवेश को प्रभावित करता है।

→ सरकारी और निजी निवेश को संतुलित करना, निर्यात को बढ़ाना, और स्थायी विकास की ओर बढ़ना इस संकट से उबरने के मुख्य रास्ते हो सकते हैं। 

4. भारत में रक्षा स्वदेशीकरण और नवाचार: आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम

✳ क्यों जरूरी है रक्षा स्वदेशीकरण?

- ✓ **राष्ट्रीय सुरक्षा:** विदेशी हथियारों पर निर्भरता कम होने से भारत संकट के समय तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है।
- ✓ **आर्थिक विकास:** रक्षा उत्पादन से स्थानीय उद्योग, MSME और स्टार्टअप को बढ़ावा मिलता है, जिससे

रोजगार और नवाचार को प्रोत्साहन मिलता है।

- ✓ **वैश्विक प्रभाव:** भारत का रक्षा निर्यात लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसकी रणनीतिक स्थिति मजबूत हो रही है।
- ✓ **आपूर्ति शृंखला सुदृढ़ता:** घरेलू उत्पादन से वैश्विक आपूर्ति बाधाओं और प्रतिबंधों का प्रभाव कम होता है।
- ✓ **तकनीकी नवाचार:** iDEX और ADITI जैसे प्लेटफॉर्म स्टार्टअप्स को उन्नत रक्षा तकनीक में काम करने का मौका दे रहे हैं।

स्वदेशीकरण और आधुनिकीकरण की सफलता

- ◆ 65% रक्षा उपकरण अब भारत में बनते हैं।
- ◆ ATAGS तोपों के लिए ₹7,000 करोड़ का ऑर्डर दिया गया।
- ◆ रक्षा उत्पादन ₹1.27 लाख करोड़ तक पहुँच गया – 174% वृद्धि!
- ◆ रक्षा निर्यात 10 साल में 30 गुना बढ़कर ₹21,083 करोड़ हुआ।
- ◆ 100 से अधिक देशों को भारत रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है।
- ◆ उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु रक्षा गलियारों में ₹8,600 करोड़ का निवेश।

चुनौतियाँ और समाधान

 **तकनीकी कमी:** इंजन, अर्द्धचालक और उन्नत रडार जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों का आयात अभी भी ज़रूरी।

💡 **समाधान:** अनुसंधान एवं विकास (R&D) में निवेश बढ़ाया जाए, निजी कंपनियों के साथ साझेदारी हो।

 **निजी क्षेत्र की सीमित भागीदारी:** रक्षा उत्पादन में निजी कंपनियों का योगदान केवल 21%।

💡 **समाधान:** स्टार्टअप्स और MSMEs को तेज़ मंजूरी और वित्तीय सहायता मिले।

 **जटिल खरीद प्रक्रियाएँ:** रक्षा उपकरणों की खरीद में देरी होती है, जिससे आधुनिकीकरण प्रभावित होता है।

💡 **समाधान:** एकीकृत परियोजना टीमों बनाई जाएँ और खरीद की समयसीमा घटाई जाए।

 **कम अनुसंधान निवेश:** भारत का रक्षा अनुसंधान बजट वैश्विक स्तर पर कम।

💡 **समाधान:** DRDO, निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के साथ मिलकर अत्याधुनिक अनुसंधान को बढ़ावा देना।

 **आयात निर्भरता:** SIPRI रिपोर्ट के अनुसार, भारत अभी भी दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक।

💡 **समाधान:** सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची का पालन किया जाए और स्थानीय निर्माण पर ज़ोर दिया जाए।

 **सरकारी पहल जो भारत को बना रही हैं रक्षा महाशक्ति**

- ✓ मेक इन इंडिया (रक्षा) – रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर केंद्रित।
- ✓ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (DAP) 2020 – घरेलू खरीद को प्राथमिकता।
- ✓ iDEX और TDF योजनाएँ – स्टार्टअप्स और MSMEs को समर्थन।
- ✓ SRIJAN पोर्टल – स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन मंच।
- ✓ रक्षा औद्योगिक गलियारे – विशेष रक्षा हब विकसित किए जा रहे हैं।

 भविष्य की दिशा: आत्मनिर्भर भारत की ओर

 R&D और तकनीकी नवाचार को प्राथमिकता देना।

 निजी क्षेत्र और MSME की भागीदारी बढ़ाना।

 तेज़ और पारदर्शी रक्षा अधिग्रहण प्रणाली बनाना।

 परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं का विस्तार करना।

 निष्कर्ष: भारत रक्षा स्वदेशीकरण में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन आत्मनिर्भरता पूरी तरह हासिल करने के लिए नवाचार, निवेश और प्रभावी नीतियों की निरंतर आवश्यकता है।  IN

5. 🌞 भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का सतत उपयोग: वर्तमान प्रगति, चुनौतियाँ और भविष्य की राह

 भारत की सौर ऊर्जा में तेज़ी से वृद्धि

- भारत सौर ऊर्जा क्षमता में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है।
- 2018 में 21.6 GW से बढ़कर 2023 तक 70.10 GW और 2030 तक 280 GW का लक्ष्य।
- PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए ₹75,021 करोड़ आवंटित।
- PLI योजना से घरेलू उत्पादन बढ़ा, 47 GW क्षमता का समर्थन और 1 लाख से अधिक नौकरियाँ।
- सोलर पार्क: 2025-26 तक 50 पार्कों में 38 GW क्षमता का लक्ष्य, 11 पार्कों में पहले ही 10,237 MW सक्रिय।
- नई तकनीकें: फ्लोटिंग सोलर, स्मार्ट पैनल और बाइफेसियल मॉड्यूल्स से उत्पादन बढ़ा।

मुख्य चुनौतियाँ

- भंडारण महंगा → बैटरियों के कारण सौर ऊर्जा की 24x7 उपलब्धता कठिन।
- ग्रिड स्थिरता → ज्यादा सौर उत्पादन से वोल्टेज अस्थिरता और डिस्कॉम घाटे की समस्या।
- नीतिगत अनिश्चितता → नेट मीटरिंग और सब्सिडी में बदलाव से निवेशक हिचकते हैं।
- आयात निर्भरता → सोलर मॉड्यूल और सेल के लिए चीन पर निर्भरता।
- तकनीकी अंतराल → हाइब्रिड इनवर्टर और बैटरी मानकों की कमी।
- पर्यावरणीय प्रभाव → सौर परियोजनाओं से जैव-विविधता और कृषि पर असर।

भविष्य के लिए रणनीतिक उपाय

- ☐ टाइम-ऑफ-डे टैरिफ → ऊर्जा मांग के अनुसार दरें तय हों।
- ☐ स्मार्ट इनवर्टर अनिवार्यता → ग्रिड संतुलन और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए।
- ☐ PM-KUSUM और RTS योजना का एकीकरण → सौर ऊर्जा को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचाना।
- ☐ सौर पारिस्थितिकी तंत्र पोर्टल → सौर ऊर्जा की सिंगल विंडो व्यवस्था।
- ☐ घरेलू विनिर्माण → सिर्फ मॉड्यूल ही नहीं, बल्कि पूरी सौर सप्लाय चेन पर ध्यान।

निष्कर्ष

भारत स्वच्छ ऊर्जा क्रांति में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ग्रिड स्थिरता, भंडारण लागत और नीतिगत स्पष्टता पर ध्यान देना ज़रूरी है। नवाचार, नीतिगत सुधार और मजबूत बुनियादी ढाँचे से भारत दुनिया का अग्रणी सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है!  

1. मानसून और क्लाउड बैंड: प्रभाव और अध्ययन निष्कर्ष

 Search

THE  HINDU

FREE TRIAL **SUBSCRIBE** LOGIN 

ADVERTISEMENT

HOME / NEWS / CITIES / BENGALURU

Strength of cloud band influences movement and density of rains during Indian monsoon, finds IISc study

Updated - March 24, 2025 08:33 pm IST - Bengaluru

THE HINDU BUREAU

 READ LATER  PRINT

Most Popular

 Three policemen killed, three security personnel

चर्चा में क्यों?

IISc के अध्ययन में पाया गया कि **क्लाउड बैंड (मेघ पट्टिकाएँ)** मानसून की दिशा और वर्षा की तीव्रता तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं।

मुख्य निष्कर्ष

मेघों की प्रबलता

- केवल **मजबूत क्लाउड बैंड** ही भारत तक पहुँचकर बारिश लाते हैं।
- कमजोर बैंड उत्तर की ओर बढ़ नहीं पाते, जो पुराने मॉडलों के विपरीत है।

वर्षा और BSISO प्रभाव

- बारिश की अवधि और तीव्रता **रेन बैंड के आकार और ताकत** पर निर्भर करती है।
- BSISO** (बोरियल समर इंटरासीजनल ऑसिलेशन) भूमध्य रेखा से भारत तक मानसूनी वर्षा लाने में मदद करता है।

वायु-समुद्र अंतःक्रिया

- हिंद महासागर में आद्रता वृद्धि और वायुप्रवाह मानसून को तीव्र करता है।

जलवायु परिवर्तन प्रभाव

- गर्म होते वायुमंडल से आद्रता और वर्षा की तीव्रता बढ़ेगी।
- भविष्य में भारत और आस-पास के समुद्रों में **42% से 63% अधिक वर्षा** होने की संभावना।

◆ जलवायु मॉडल में सुधार

- अध्ययन से मानसून पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाने में मदद मिलेगी।

🌐 BSISO और ENSO का प्रभाव

- BSISO मानसून के सक्रिय (वर्षा) और ब्रेक (शुष्क) चरणों को नियंत्रित करता है।
- ENSO प्रभाव:
 - ला नीना → मानसूनी गतिविधियाँ मजबूत होती हैं।
 - अल नीनो → मानसून कमजोर पड़ता है।

🌩 भारत में मानसून के मुख्य तथ्य

✓ दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून-सितंबर)

- हिंद महासागर से नमी लाकर भारी बारिश करता है।
- तिब्बत पर कम दबाव और समुद्र पर उच्च दबाव इसकी प्रमुख वजहें।

✓ पूर्वोत्तर मानसून (अक्टूबर-दिसंबर)

- तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश में बारिश लाता है।
- दक्षिण-पश्चिम मानसून के वापसी से जुड़ा होता है।

✓ मुख्य कारक

- ITCZ (अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र) मानसून को प्रभावित करता है।
- तिब्बती पठार की गर्मी उष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम को जन्म देती है।
- IOD (हिंद महासागर द्विध्रुव) और ENSO (अल नीनो-ला नीना) मानसून को मजबूत या कमजोर करते हैं।

✨ निष्कर्ष

क्लाउड बैंड और BSISO की भूमिका समझकर मानसून पूर्वानुमान को और सटीक बनाया जा सकता है। साथ ही, जलवायु परिवर्तन और महासागरीय प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर नीतियाँ तैयार करनी होंगी ताकि मानसूनी अनिश्चितताओं से निपटा जा सके। 🌩 ⚡

2. 🚀 सहयोग पोर्टल और एक्स कॉर्प का विरोध

🏛️ मामला क्या है?

एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) ने भारत सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिसमें IT अधिनियम, 2000 की धारा 79 और नए सहयोग पोर्टल के माध्यम से कंटेंट सेंसरशिप को चुनौती दी गई है।

एक्स का तर्क:

- कंटेंट हटाने के आदेश केवल IT अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी होने चाहिए।
- सहयोग पोर्टल IT कानूनों की सीमा से बाहर जाकर सेंसरशिप को बढ़ावा देता है।

📌 सहयोग पोर्टल क्या है?

गृह मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया यह पोर्टल सरकारी एजेंसियों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए बनाया गया है।

✎ मुख्य कार्य:

- ✓ गैर-कानूनी कंटेंट की रिपोर्टिंग और हटाने की प्रक्रिया को आसान बनाना।
- ✓ कानून प्रवर्तन एजेंसियों को डेटा अनुरोधों में सुविधा प्रदान करना।
- ✓ सोशल मीडिया कंपनियों और सरकारी एजेंसियों को एक मंच पर लाना ताकि अवैध डिजिटल गतिविधियों पर तेजी से कार्रवाई हो सके।

📖 IT अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ

✎ धारा 69A

👉 केंद्र सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने का अधिकार देती है।

✎ धारा 79

👉 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को "सेफ हार्बर" (कानूनी संरक्षण) प्रदान करती है, यदि वे तटस्थ रूप से काम करें।

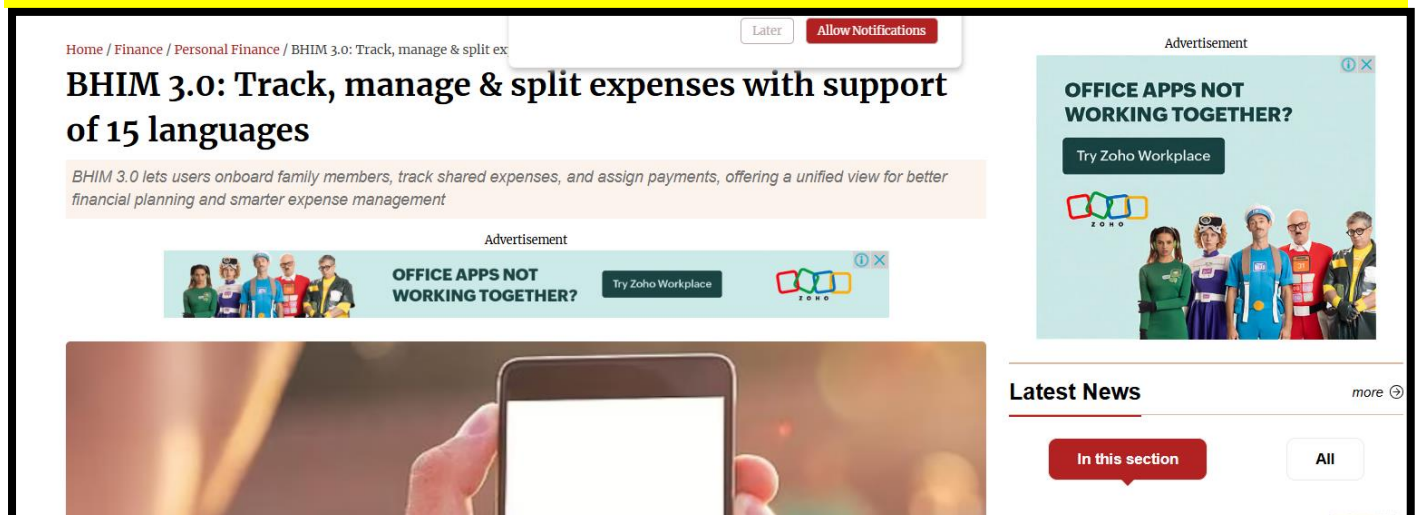
👉 धारा 79(3)(b) के तहत, अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनुचित कंटेंट हटाने में देरी करता है, तो वह कानूनी सुरक्षा खो सकता है।

😊 इसका असर क्या होगा?

- यदि एक्स कॉर्प का मुकदमा सफल होता है, तो सरकार की सोशल मीडिया विनियमन शक्तियों पर प्रभाव पड़ सकता है।
- अगर सहयोग पोर्टल को मान्यता मिलती है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सख्त निगरानी संभव होगी।
- डिजिटल सेंसरशिप और फ्री स्पीच को लेकर बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो सकता है।

👉 आपका क्या मत है – सहयोग पोर्टल साइबर सुरक्षा के लिए सही कदम है या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध? 💬

3. 🚀 BHIM 3.0 – डिजिटल भुगतान का नया युग



NPCI BHIM सर्विसेज़ लिमिटेड (NBSL) ने BHIM 3.0 ऐप लॉन्च किया है, जो डिजिटल भुगतान को और तेज़, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाता है।

📌 BHIM 3.0 क्या है?

👉 BHIM (भारत इंटरफेस फॉर मनी), UPI तकनीक पर आधारित एक कैशलेस भुगतान ऐप है, जिसे 2016 में लॉन्च किया गया था।

👉 यह बैंक अकाउंट डिटेल्स शेयर किए बिना मोबाइल से तुरंत पैसा भेजने और प्राप्त करने की सुविधा देता है।

👤 BHIM 3.0 की नई विशेषताएँ

- ✓ 15+ भाषाओं में उपलब्ध – स्थानीय भाषाओं में उपयोग आसान।
- ✓ कम इंटरनेट पर भी काम करेगा – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी उपयोगी।

- ✓ बेहतर सुरक्षा – डिजिटल धोखाधड़ी से सुरक्षा बढ़ी।
- ✓ व्यक्तिगत वित्त प्रबंधन –
 - खर्च को ट्रैक करने के लिए स्प्लिट एक्सपेंस और एनालिटिक्स।
 - लंबित बिलों के लिए अनुस्मारक (रिमाइंडर)।
- ✓ व्यापारियों के लिए – BHIM वेगा
 - इन-ऐप पेमेंट सिस्टम – बिना किसी अन्य ऐप के लेनदेन की सुविधा।

💡 BHIM और NPCI का वैश्विक विस्तार

✈️ NPCI की स्थापना (2008) – RBI और भारतीय बैंक संघ द्वारा खुदरा भुगतान प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए की गई।

✈️ UPI अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रिय – अब भूटान, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और फ्रांस में भी उपलब्ध।

✈️ PhonePe, Paytm, Google Pay जैसे 20 ऐप्स के जरिए अंतराष्ट्रीय भुगतान संभव।

🌐 डिजिटल इंडिया के लिए BHIM 3.0 क्यों महत्वपूर्ण?

💰 कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा

📊 छोटे व्यापारियों और ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल भुगतान की पहुंच

🔒 साइबर सुरक्षा के साथ तेज़ और सुरक्षित ट्रांज़ैक्शन

💬 क्या BHIM 3.0 डिजिटल भुगतान में गेम चेंजर साबित होगा? 😊

4. 🏆 स्वर्ण मुद्राकरण योजना – महत्वपूर्ण बदलाव

💎 सरकार ने स्वर्ण मुद्राकरण योजना (GMS) के तहत

👉 मध्यावधि (5-7 वर्ष) और दीर्घकालिक (12-15 वर्ष) जमा योजनाएँ बंद कर दी हैं।

👉 अल्पकालिक बैंक जमा (1-3 वर्ष) जारी रहेंगी।

💎 स्वर्ण मुद्राकरण योजना (GMS) क्या है?

 शुरुआत – 15 सितंबर 2015

 उद्देश्य –

☒ सोने के आयात पर निर्भरता कम करना

☒ घरेलू और संस्थागत स्वर्ण भंडार को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाना

☐ पूर्व GMS योजनाएँ:

- अल्पकालिक बैंक जमा (1-3 वर्ष) – ब्याज दर बैंक तय करते हैं
- ☒ मध्यावधि सरकारी जमा (5-7 वर्ष) – (2.25% ब्याज) (अब बंद)
- ☒ दीर्घकालिक सरकारी जमा (12-15 वर्ष) – (2.5% ब्याज) (अब बंद)

 सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) भी बंद

 शुरुआत – 2015

 उद्देश्य –

☒ भौतिक सोने की मांग कम करना

☒ घरेलू बचत को वित्तीय निवेश में बदलना

 लाभ –

 2.5% ब्याज दर (हर 6 महीने में बैंक खाते में जमा)

 इस बदलाव का असर क्या होगा?

☐ सोने की नकद खरीदारी बढ़ सकती है

 बचत योजनाओं में विविधता की आवश्यकता बढ़ेगी

 स्वर्ण भंडारण को औपचारिक अर्थव्यवस्था में लाने की चुनौती

? क्या आपको लगता है कि यह फैसला भारत की सोने पर निर्भरता को कम कर पाएगा? 

5. बायोसारथी मेंटरशिप पहल और भारत की जैव-अर्थव्यवस्था

 विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र में स्टार्ट-अप्स के लिए "बायोसारथी मेंटरशिप पहल" शुरू की।

 साथ ही, "इंडिया बायोइकोनॉमी रिपोर्ट 2025" (IBER 2025) जारी की गई।

 बायोसारथी मेंटरशिप पहल क्या है?

- ◆ 6 महीनों का कोहॉर्ट प्रोग्राम, जिसमें उभरते जैव-प्रौद्योगिकी उद्यमियों को व्यक्तिगत मार्गदर्शन मिलेगा।
- ◆ उद्योग और अकादमिक सहयोग को मजबूत करने पर जोर।
- ◆ विदेशों से भारतीय विशेषज्ञों को मेंटर के रूप में शामिल किया जाएगा।

 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था – 2025 लक्ष्य

 वृद्धि:

2014 – \$10 बिलियन → 2024 – \$165.7 बिलियन (16 गुना वृद्धि)

 GDP में योगदान: 4.3%

 मुख्य क्षेत्रीय योगदानकर्ता:

- दक्षिण भारत (45.40%)
- राज्य: कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश

 बायोटेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टम की वृद्धि:

 2014: केवल 50 स्टार्ट-अप

 2024: 10,075+ स्टार्ट-अप

 प्रमुख सरकारी पहलें

 BioE3Policy, 2024 – जैव-अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार को बढ़ावा।

 Bio-RIDE, 2024 – जैव प्रौद्योगिकी नवाचार और उद्यमिता विकास।

✈️ राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (NBM), 2017

✈️ राष्ट्रीय जैव-अर्थव्यवस्था मिशन, 2016

🏆 प्रमुख वैज्ञानिक उपलब्धियाँ

❑ "नेफिथ्रोमाइसिन" – रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) से लड़ने के लिए भारत का स्वदेशी एंटीबायोटिक।

❑ "जिनी" – व्यक्तिगत स्वास्थ्य अंतर्दृष्टि के लिए एक अनुकूलित जीनोमिक्स प्लेटफॉर्म।

💉 "Quatenty CAR T-cell Therapy" – नॉन-हॉजकिन लिंफोमा के इलाज के लिए इम्यूनील थेरेप्यूटिक्स द्वारा लॉन्च की गई।

🧠 भारत की जैव-अर्थव्यवस्था का भविष्य

🌐 क्या भारत 2030 तक जैव-अर्थव्यवस्था में वैश्विक अग्रणी बन सकता है?

💡 स्टार्ट-अप्स, नवाचार और सरकारी नीतियाँ इस लक्ष्य को कितना आगे ले जा सकती हैं?

आपका क्या विचार है? 🚀 🤖